

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, भदोही-ज्ञानपुर।

फौजदारी अपील सं०- 17 सन 2017,

1. लाल बहादुर पाल पुत्र स्व० नेपाल पाल निवासी शेरपुर गोपलहा थाना दुर्गागंज जिला भदोही..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजन पक्ष

फौजदारी वाद सं० 3788 सन 2015

अ० सं० 81 सन 2015

धारा-419,420,409,467,468,471 भा० दं० सं०।

थाना दुर्गागंज जिला भदोही।

1. अभियुक्त/अपीलार्थी लाल बहादुर पाल पुत्र स्व० नेपाल पाल निवासी शेरपुर गोपलहा थाना दुर्गागंज जिला भदोही की तरफ से फौजदारी वाद सं० 3788 सन 2015 अ० सं० 81 सन 2015 धारा-419,420,409,467,468,471 भा० दं० सं० थाना दुर्गागंज जिला भदोही के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र 6 ख एवं जुमाने एवं दण्डादेश के स्थगन हेतु प्रार्थनापत्र 8 ख प्रस्तुत किया गया।

2. अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को उपरोक्त प्रकरण मे धारा 467/120 बी,468/120,471/120 बी भा० दं० सं० के अन्तर्गत सात वर्ष का साधारण कारावास तथा धारा 419 भा० दं० सं० के तहत दो वर्ष के साधारण कारावास व धारा 420 भा० दं० सं० के तहत चार वर्ष के साधारण कारावास तथा दो लाख पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। जो सूची तैयार की गयी थी वह शेषमनी पाण्डेय ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा तैयार की गयी थी उसमें अपीलार्थी की कोई भूमिका नहीं थी। निर्णय में लाभार्थियों की संख्या के योग में त्रुटि पर ध्यान नहीं दिया गया है। गवाह राजन शुक्ला पी० डब्लू००६ की अभियुक्त/अपीलार्थी से रंजिश के विन्दु पर

अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया। पी0 डब्लू010 गौतिया देवी आरोप पत्र में गवाहों की सूची में नहीं थी। अभियोजन द्वारा उन्हें न्यायालय में प्रथम बार परीक्षित कराया गया है। तथा इसी आधार पर जमानत की माँग की है और जुर्माने को अपील के सुनवाई तक स्थगित किये जाने की प्रार्थना की है।

3. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत अपील को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 की उपधारा 2 के तहत इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। तथा दण्डाधिकारी द्वारा दण्डादेश द0 प्र0 सं0 की धारा 31 के तहत पारित किया गया है। तथा अभियुक्त विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहा है। तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतः विधि संमत एवं तर्क पूर्ण है। इसलिए अपीलार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए। तथा दण्डादेश एवं जुर्माने का क्रियान्वयन स्थगित न किया जाए।

4. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में प्रभात कुमार श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी के पत्र प्रदर्शक-2 से यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है कि लाल बहादुर पाल तथा शेषमणि पाण्डेय के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। तथा जाँच रिपोर्ट प्रदर्शक-1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें सेक्टर प्रभारी श्री कृष्ण कुमार को इन्द्रा आवासों की पात्रों की जाँच न करने का दोषी, श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव को लाभार्थियों का मिलान न करने का दोषी, भी पाया गया। परन्तु इन्हीं प्रभात कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। तथा प्रदर्शक-20 डी0 डब्लू01 फतेलाल की जिरह में पेज 7 दिनांक 17.08.2016 को उलाया गया है।

जिस पर बचाव पक्ष ने आपत्ति की है। तथा इस पर निर्णय के पृष्ठ 63 पर अधीनस्थ न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि वह प्रधान दायित्व था कि वह उसे देखता लेकिन यह जानबुझकर न देखना षडयन्त्र की बू आ रही है। जब कि अभियुक्त प्रधान नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन विन्दुओं पर दिये अभिमत पर अपील में सुनवाई की आवश्यकता है। जहाँ तक धारा 374(2) के प्रावधान का प्रश्न है। यह अधिकार अभियुक्त का है कि वह माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करेगा या सत्र न्यायाधीश के यहाँ। अभियोजन की यह आपत्ति मान्य नहीं है कि अपील पर सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। और उपरोक्त विन्दुओं के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त दौरान अपील जमानत का अधिकारी है और दण्डादेश व जुर्माने का क्रियान्वयन स्थगित किये जाने योग्य है।

#### आदेश

अपीलार्थी/अभियुक्त लाल बहादुर पाल फौजदारी वाद सं० 3788 सन 2015 अ० सं० 81 सन 2015 धारा-419,420,409,467,468,471 भा० दं० सं०। थाना दुर्गागंज जिला भदोही में सम्बन्धित मजि० के समक्ष मु० 50,000/रूपये की दो जमानते एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर रिहा किया जाए। तथा दौरान अपील जुर्माने की वसूली स्थगित रहेगी।

अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय,

भदोही-ज्ञानपुर।

14.12.2017